At Transforming India Program in Mumbai with Arun Jaitley Ji
20.08.2016

धन्यवाद आशीष जी, सम्मानीय अरुण जेटली जी, बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं सामने, वास्तव में मेरे लिए तो घर वापसी है, I am back amongst my friends. मैं तो आज खुद सुनने आया था वित्त मंत्री जी को, उनके सम्बोधन को, हर बार जब उनको सुनते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए मैं सिर्फ एक-दो चीजें आपके समक्ष रखूँगा | अगर इस सरकार के दो वर्ष के कार्य काल में सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ हुई है वो है mindset change, सोचने का जो नजरिया है, बहुत आसन होता हम सरकार में आए, दिल को लुभाने वाली बातें करें, दिल को लुभाने वाले काम करें, लोगों को ऐसा लगे रिज़र्व बैंक अपने आप नोट छाप-छाप के बाँट दे, शोर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हरियाली ही हरियाली है लेकिन इस सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, वित्त मंत्री जी की जो सोच है कि हमें एक ज़िम्मेदारी मिली है और इस ज़िम्मेदारी से हमें देश की अर्थव्यवस्था 20 साल, 40 साल, 50 साल आगे की सोचकर कैसे एक आधारभूत व्यवस्था बनानी है, how do we improve the framework of governance so that the people at large are assured that not for one or two or five years, one term of this government or two terms of this government but for a sustainable development agenda which gives us decades of prosperity. The effort has been that we focus on principles of good governance, the effort has been that every action of this government leaves behind a legacy and a legacy on which this country can see possibly double-digit growth for the next 20, 30, 40 years. And that, the honorable Prime Minister also spoke from the ramparts of the Red Fort and all the issues that he raised were a reflection of this changed mindset. So when a person comes to Mr Jaitley with a problem he does not try to solve that problem, he tries to see what is the root cause of that problem, resolve the root cause of that problem and in that sensethe structural change that honorable Finance Minister has tried to bring in in the working of the tax department, in the way different Finance Ministry-related issues are administered. I would only like to compliment Arun Jaitley ji, उन्होंने मेरे ख्याल से मन का जो परिवर्तन किया पूरे देश में और अगर सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिने तो मैं समझता हूँ हम सभी GST का स्वागत करते हैं, हम सबने GST के लिए उनका अभिनन्दन करना है | मैं समझता हूँ Goods and Services Tax में वो सम्भावना है कि वो इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था को भी मज़बूत बनाएगा और taxation के system को इतना सरल और इतना ईमानदार कर सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए सभी, हो सकता है मेरे मित्र Chartered Accountant थोडा नाराज़ हो सकते हैं, उनका काम काज कम होगा थोडा बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ इस देश के पूरे जनता के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए और आगे चलके इस देश के आगे की अर्थव्यवस्था को और मज़बूत बनाने में ऐतिहासिक कदम होगा | सर्व सहमति से पास होना ये सिर्फ वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की कुशल नेतृत्व का एक symbol है | हर एक वर्ग को, हर एक राज्य को, हर एक पार्टी को साथ में लेना और ये विश्वास पैदा करना कि इस केंद्र सरकार पे आप विश्वास कर सकते हो, यह नेतृत्व, जो कहता है ये नेतृत्व वो deliver करेगा, इस प्रकार का जो प्रधानमंत्री मोदी जी और जेटली जी की टीम ने इस पूरे GST कानून को पास करवाने के दौरान जो कुशल नेतृत्व दिया है मैं पुनः एक बार मोदी जी और जेटली साहब को बधाई देके अपनी बात को विराम देता हूँ |

बहुत बहुत धन्यवाद !

Speech by Arun Jaitley ji

मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष जी, मंत्री श्रीमती विद्या ठाकुर जी, सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, मेरे मित्र और सहयोगी पीयूष जी, श्री बी. सतीश, मंच पर बैठे हुए मुंबई के कई हमारे विधायक साथी, पार्टी के प्रमुख नेता गण और मित्रों, कई बार किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब उन अवसरों का लाभ उठा पाना, उन opportunities को seize कर लेना व्यापक देश हित में होता है | लेकिन अपने देश का एक दुर्भाग्य रहा कि कई बार ऐसे अवसर आए और हम प्रायः उन अवसरों को खोते रहे, अगर हम इतिहास के पुराने पन्ने देखें तो भाषणों में तो हम लोग ये मानते रहे कि एक वक़्त था भारत का पूरे विश्व में बहुत बड़ा रोल था लेकिन जब पहली industrial revolution आई और यूरोप, अमेरिका, ये सब विकसित क्षेत्र बन गए दुनिया के तो हमें छुए बगैर वो उद्योगी क्रांति निकल गई | और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो मानता है कि स्वतंत्रता के बाद जो आर्थिक रास्ता हम लोगों ने अपनाया था वो अपने आप में बहुत विकास के रास्ते पे इस देश को ले जाता वो रास्ता नहीं था और शायद यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहले तीन-चार दशक रहे उसमें 1, 1.5, 2% बहुत हुआ तो 2.5% growth हो गई और पूरे विश्व में भारत की तरफ जब देखते थे तो किसी गिनती में हम लोग नहीं आते थे, पूरे विश्व में जितने economies थे वो व्यंग में, sarcasm में कभी भारत का जिक्र भी करते थे तो हमारी 2-2.5% की जो growth होती थी, 60 के, 70 के दशक में, तो उसको Hindu rate of growth कहते थे | Hindu rate of growth became an economic phenomena और लोगों को लगता था कि ये रास्ता आगे बढ़ने वाला नहीं है लेकिन उस वक़्त mindset ये था कि सरकार की सारी ज़िम्मेदारी है और निजी व्यापर, उद्योग इसका एक बहुत सीमित रोल है उसके बाद दुनिया के कई अन्य देश जो यूरोप और अमेरिका से बाहर थे और ये लोग मानते थे कि ये क्षेत्र अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं ये कभी विकास कर नहीं सकते लेकिन दूसरे महा युद्ध के बाद स्थिति बदली | पहला अनुभव जापान का था, कोरिया का था, ताइवान का था, ये एशिया के देश थे और छोटे देश थे और इन तीनों देशों ने technology का इस्तेमाल करके, technology के माध्यम से जो innovations किए और अपने देश की economy को पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया. For them the whole world was a market. They were aiming high. और इसीलिए पूरे एशियाई देशों ने इसको एक उदाहरण की तरह set किया और वो उदाहरण ये था कि आप technology के माध्यम से, innovations के माध्यम से पूरी global economy के साथ integrate कर सकते हो, पूरी दुनिया को अपना एक बाज़ार बना सकते हो | जब वो सफलता के रास्ते पे थे तो हम लोग एक दूसरे mindset में जी रहे थे, we were actually impacted by the Nehruvian thought और हमें लगता था कि कुछ काम ऐसे हैं सिर्फ सरकार करेगी | अब 1947 से लेकर 1995 तक लगभग 50 वर्ष तक हमने कहा कि टेलीफोन देना लोगों को ये सिर्फ सरकार का काम है and all we achieved in the first 50 years was that 0.8%. जो लोग उस economy सोच की प्रशंसा आज भी करते हैं कम से कम उनको ये सोचना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर आने के बाद 20 साल में वो 80% से ज्यादा चला गया लेकिन सरकार ने जब तक अपने हाथों में रखा तो we couldn't even touch 1% और ये एक उदाहरण है लेकिन लगभग हर क्षेत्र की यही कहानी थी | उस सोच में से हम जो बाहर निकले वो भी मजबूरी में बाहर निकले ये नहीं था कि नरसिम्हा राव जी विचार से बहुत बड़े liberalizer थे, मैं अभी उनके ऊपर जो पुस्तक आई पढ़ रहा था उसमें एक मैंने बड़ी विचित्र चीज़ पढ़ी कि जब वो आंध्र प्रदेश के Education Minister बने तो उनका पहला निर्णय था कि all private colleges should be abolished only government will run colleges. तो original thought उनका भी यही था |

इसमें विशेष रूप से, पहले कह सकते हैं कि 50 के, 60 के दशक में साधन कम थे, लेकिन 70 और 80 का जो दशक था वो तो wasted decades थे उसमें लगता था कि केवल नारों के आधार पर राजनीति चलेगी और जो ये सोच के समर्थक थे उनको लगता था क्या आप जापान का और कोरिया और ताइवान का उदाहरण दे रहे हो, छोटे से देश हैं बहुत कम जनसँख्या है लेकिन इस सोच

को चोट तब पहुंची जब चाइना ने भी अपनी इकॉनमी बदल दी और चाइना का इकनोमिक जो स्ट्रक्चर था, जनसँख्या भी तो थी वो भारत की तरह ही थी और जब 80 के दशक में चाइना ने अपना रास्ता बदल लिया तो उस पुराने विचार के जो समर्थक थे अब उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं बचा | China was no Korea or Taiwan. और फिर उसने प्रगति करनी शुरू की तो लगभग 30 साल तक उन्होंने एक दूसरा वैकल्पिक मॉडल ढूँढा और उनका वैकल्पिक मॉडल था कि mass scale manufacturing, low cost manufacturing और उन्होंने उस low cost और mass manufacturing को पूरी दुनिया के बाज़ार के साथ छोड़ दिया and China became the global factory. विचार का कोई स्थान नहीं बचा, नरसिम्हा राव जी की सरकार फिर वाजपेयी जी की सरकार धीरे-धीरे उसको आगे बढाती रही लेकिन 2004 से 2014 की जो अवधि है और इसमें विशेष रूप से जो UPA-I में ये लगता था कि ये लेफ्ट पार्टीज भी समर्थन कर रही हैं इसलिए थोडा धीरे चल रहे हैं, लेकिन फिर रास्ते से भटकने की हम लोगों ने कोशिश की और उस भटकती हुई कोशिश का एक असर ये था कि उस सरकार को लगता था कि you don't have to increase productivity, you don't have to concentrate on increasing productivity but you have to concentrate only on redistribution और जो National Advisory Council का अनुभव था वो लगभग इसी प्रकार का था | इस पृष्ठ भूमि में 2014 में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन में स्वाभाविक कुछ लाभ भी थे पहला लाभ ये था कि 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत वाली एक सरकार केंद्र में बनी, दूसरा लाभ था कि सरकार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में था जिसमें कठोर निर्णय ले पाने की क्षमता भी थी और मैं ये मानता हूँ कि हमने जिस प्रकार से पहला अवसर इतिहास का, industrial revolution का उसका लाभ नहीं उठाया, technology revolution आया उसका लाभ नहीं उठाया, low cost manufacturing एक तीसरा अवसर था उसका लाभ नहीं उठाया तो किसी देश के जीवन में इतने अवसर नहीं मिलते और शायद आज इस देश को आज की इस विश्व की परिस्थिति में एक अवसर पुनः मिला and what is that opportunity? आज अगर हम पूरी दुनिया की स्थिति देखें तो क्या है कि सच में 2008 की global economic crisis के बाद पूरी ताक़त के साथ तो कभी विश्व की अर्थव्यवस्था उठ ही नहीं पाई | The global economy is poised in a situation where there is very low demand, oil prices have collapsed, commodity prices have gone down, mineral prices have gone down. And nobody in the world is certain how long this phase is going to last. जब पूरी यूरोपियन इकॉनमी उठ नहीं पाई, अमेरिका की जो growth है, job growth कई बार बढती है और फिर उनको लगता है कि जैसे इस बार लगता था 2% American economy बढ़ेगी, वो फिर कम बढ़ी, It's patchy | चाइना जो 30 साल तक 9% औसतन पे grow करता रहा and China was shouldering 50% of the global growth. आज चाइना का नेतृत्व कहता है The new Chinese normal is no longer 9% it is 7%. लेकिन जो वास्तविक डेटा आता है वो उससे भी नीचे आता है, 6%, 6.5% की range में बात होती है | जो भारत के साथ कम्पीट करती थी अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील नेगेटिव में है, रशिया नेगेटिव में है, जो हमारी BRICS की economies थीं | तरह-तरह के तरीके इस्तेमाल कर रही है, कभी कल्पना नहीं थी कि ब्याज दर नेगेटिव हो जाएगा, अब $100 बैंक में रखेंगे तो $99 वापिस मिलेगा | जापान में नेगेटिव हो गया, BREXIT के बाद ब्रिटेन में अभी 0.25%, एक दम flat interest rateहै, unconventional तरीके दुनिया इस्तेमाल कर रही है अपनी currency को बार-बार सस्ती करती है ताकि trade को उससे मदद मिले | Global trade एक दम shrink कर गया और उस shrinkage का असर हम पे भी होता है | कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था तीन साल पहले कि एक आर्गुमेंट दी जाएगी that the world needs higher oil prices in order to grow. लोगों को लगता था तेल का दाम कम होगा तो बेहतर होगा अब लोगों को लगता है थोडा बढेगा तो शायद ग्रोथ हो जाए | अब इस परिस्थिति में हम कहाँ खड़े हैं जिसको इतने दशकों तक कहते रहे कि ये Hindu rate of growth है फिर कहा कि आपने रिफॉर्म्स किए फिर रुक गए, फिर, India's appetite for reforms itself was a

suspect और long term sustained reforms कर पाना, अपने आप में इसको लेकर प्रश्न चिन्ह था | अब इस परिस्थिति में इस सारे का असर हम पे क्या है ? इस सारे का असर हमपे ये है कि जो नुकसान हम पे है वो स्पष्ट है कि जब पूरे विश्व का ट्रेड श्रिंक करता है तो स्वाभाविक है हमारा भी करेगा | अगर volume उतना भी रहे लेकिन मिनरल्स का, तेल का अगर दाम कम होगया तो values कम हो जायेगी | It may not shrink in volume terms, it will shrink in value terms. जब Global demand कम होगी तो हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा और ये एक स्वाभाविक असर है लेकिन हम दुनिया की बहुत कम ऐसी economies हैं जिनके लिए इसमें एक opportunity भी है और वो opportunity बड़ी स्पष्ट है कि जब पूरी दुनिया कोई -2% पे है कोई +2% पे है इसी range में है हम एक मात्र दुनिया की इकॉनमी ऐसी है जो 7-8%, 7.5-8% grow करने की क्षमता रखते है | एक कहावत है अंग्रेजी में When the going is good everybody is at his best. लेकिन जब चुनौतीपूर्ण माहौल हो उस trend को defy करकर ऊपर बढ़ना ये अपने आप में कठिन होता है और किसी भी देश की resilience और क्षमता तब उसके अंदाज़ में आती हैं और मैं ये मानता हूँ कि आज इसमें हमारे लिए एक opportunity भी है और ये जो global slowdown में 7.5-8% की range में अगर भारत आ जाता है तो what happens if growth returns to the world? And the global environment is not obstructive but supportive. फिर तो स्वाभाविक है कि हम और तेज़ी से बढ़ सकते है लेकिन हमारे लिए असली चुनौती ये है कि हम एक लम्बे अवधि काल के लिए उसी स्पीड और गति के ऊपर ग्रो करें और आज भी हमारे देश में उस द्रष्टि से ग्रो करना इसकी बहुत कैपेसिटी है कारण बड़ा स्पष्ट है आज अगर हम देखें तो ग्रोथ का potential कहाँ-कहाँ है स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा infrastructure deficit है और वो infrastructure deficit अगर हम पूरा करने लगते हैं तो अभी तो हमें एक-दो दशक और लगेंगे हर साल लाखों करोड़ रूपए का निवेश डालना और किसी तरीके से उस infrastructure deficit को पूरा करना, Rural roads; हमारा target है कि 2019 तक देश का हर गाँव पक्की सड़क से कनेक्टेड हो.Railways; केवल UPA model की रेल मंत्री नई रेलें घोषित करदे बजट में और वो रेलें कभी 30-30 तक न चलें, इसके स्थान पर मौजूदा infrastructure को modernize करना, आज 400 railway station दुबारा बने, railway locomotives के plant बने, fast और superfasttrains देश के अन्दर आए कनेक्टिविटी बढाने के लिए, Power Sector; देश का कोई गाँव न रहे जहाँ बिजली न पहुंची हो और ये शायद लगता है कि 2018 से पहले ही ये target achieve कर लेगे |.

देश में सरप्लस बिजली, renewable energy और reasonable rates में उपलब्ध हो मतलब पहली बार हम power surplus की दिशा में चले जाएँ ये infrastructure का अंग है, अब इसी साल के लिए ये टारगेट बना लिया कि 35 नए regional airports देश के अन्दर बनाए जाए, in one year. अब मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा देश है जिसका Infrastructural creation का प्रोग्राम इतना ambitious होगा, अब दूसरा क्षेत्र जो growth का स्पष्ट नज़र आता है वो है rural India और rural India में भी Eastern India. मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि आप भारत के बीच में से एक लाइन खींच लीजिए, the growth on the western part of that line is much higher than the growth in the east. और इसलिए इन दोनों Regions के बीच में equity लाना है, आज प्रयास क्या है कि तरह तरह के तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में साधन पहुंचे | Rural roads, rural electrification, स्वच्छ भारत के नाम पर हर गाँव में toilet creations, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, state subject है लेकिन सेंटर भी उस irrigation program में आए जिससे productivity बढे | Rural housing, किसान की uncertainty को समाप्त करने के लिए crop insurance, interest subvention, 2022 तक rural housing. अब पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में ये होना ये अपने आप में एक एसेट है और एक बात स्पष्ट है कि जो growth engines होते हैं, वो urban centers बनते हैं, revenues भी वहां से

आता है, इसीलिए कहते हैं कि मुंबई का देश का बहुत बड़ा revenue देता है | अभी आशीष जी कह रहे थे कि GST की rate को 18 से नीचे 17 पे लाओ तो आप देश में जितने tax payer हैं अगर सभी टैक्स अपना पूरा देने लगे, तो आपकी उम्मीद को भी बेहतर कर सकते हैं, मगर इसमें स्पष्ट है the more the evasion the higher will be the rate, the more the exemptions the higher will be the rate, इसलिए moderate rates और evasion साथ-साथ नहीं coexist कर सकते, और जब हम evade करते हैं तो फिर वो tax structure में भी aberration आता है तो इसीलिए ये जो creation of new urban centres, Smart cities. और इसके पीछे एक कारण भी है अब कृषि का योगदान GDP में, agriculture contributes about 16% or so, you can't have 55% of India's population dependent on 16% of the income and therefore more and more people must get out of agriculture leaving only some members of the family to execute agriculture and get into services and manufacturing. तो अगर infrastructure creation, rural India, more urbanization और इन सब economies में चाइना में, जापान में, कोरिया में urbanization went with economic growth. और उसमें manufacturing का योगदान बढ़ाना क्यूंकि manufacturing is where mass jobs are. और इसलिए Make in India केवल एक स्लोगन नहीं है, वो job creator है, वो revenue provider है, वो देश में innovations को खड़ा करता है और केवल services sector के आधार पर देश की economy चल जाए ये संभव नहीं है और आपने ठीक कहा कि इसके लिए जितने reforms चाहिए, India's appetite at reforms is also being washed. अब अगर 26 महीने हुए हैं और कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस दिन कोई न कोई बड़ा निर्णय सरकार न करे और पिछले तीन-चार महीनों में अगर हम देखें पिछले 20 सालों से बात चल रही थी कि देश में ब्याज दर क्या हो ये Monetary Policy Committee देश की Monetary policy तय, करनी चाहिए, ऐसा नहीं था हर कोई कहता था Monetary Policy Committee बने. इस साल बजट सेसन में हमने कानून बदल के उसको बना दिया और जो एक बड़ी समस्या है higher interest rates ki अब वो कमिटी बनेगी अपने आप देखेगी कि इन्फ्लेशन लेवेल्स क्या है और कितना ब्याज दर होना चाहिए | ये एक significant reform था इतने वर्षों से pending था | मैंने जब से होश संभाला है में तबसे सुन रहा हूँ there must be rationalization of subsidies. और हर साल हम बढ़ा देते थे अब subsidies थी, मैंने उनको डिफाइन किया एक बार पार्लियामेंट में, I said these are unquantified amounts given to an unidentifiable section of people. मैंने ये कहा कि, मैंने पहले सेशन में जब मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने कहा कि अब LPG subsidy मुझे क्यूँ मिलती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, But I am a part of that unidentified section so it must be targeted only for the poor and the beneficiary. अब हर कोई 30 साल से कह रहा था लेकिन कहीं इसका implementation नहीं था तो आज हमने आधार का कानून बनवाकर कि अगर आपको सरकारी लाभ चाहिए सब्सिडी का तो, धीरे-धीरे अपना आधार नंबर लाइए, अब कोई व्यक्ति दो-दो तीन-तीन बार लेले, कोई जो पैदा नहीं हुआ वो लेले, कोई पैसे वाला, साधन वाला लेले, अब इसमें से जितनी बचत होगी वो बचत किसके पास जाएगी वो जो LPG में से बचत हुई है उसी से 5 करोड़ गरीब परिवार जो लकड़ी या कोयले का चूल्हा जलाते थे उनके पास लाभ पहुँच गया. So you had targeted subsidies जो लकड़ी और कोयले का चूल्हा है जो महिला जलाती थी मैंने बजट में इस साल कहा It is equal to smoking 400 cigarettes. This is what we were subjecting our poor people to. अब उसमें से 25 करोड़ परिवार इस देश में है 5करोड़ को हम फ्री में देंगे, ये वो पैसे की बचत है ! इस परिस्थिति में अब एक Monetary Policy Committee बनी, आधार बना, आज तक इस देश में bankruptcy का कानून ही नहीं था, पिछले सत्र में वो पास किया फिर GST पारित किया तो एक के बाद एक सरकार बड़े निर्णय करती जा रही है |

अगर आप शुरू से देखें तो हमने क्या रास्ता अपनाया हमारा रास्ता था सबसे पहले कि देश में निवेश का अकाल पड़ा हुआ है, सरकार इन्वेस्ट कर नहीं रही थी, बाहर से कोई पैसा लाना नहीं चाहता था, private sector over-stressed था जिसको ठीक करने में कुछ समय लगता | अब इसलिए पहले निर्णय हम लोगों ने लिए we liberalized the economy, तो we became the largest recipients of global investment in India. और आज भी इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी देश की अर्थव्यवस्था कम से कम दो engines पे, public investment पे बधाई, और public investment के साथ-साथ global investment इस देश के अन्दर आनी शुरू हुई और केवल खोलने से दरवाज़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती आप, you have to provide for ease of doing business, ease of doing business में पहला कदम था कि corruption कम हो, eliminate हो, निर्णय सरल हो ये UPA सरकार द्वारा FIPP महीनों तक नहीं मिलती, सालों तक environment clearance नहीं मिलती, ये सारे processes हम लोगों ने सरल किए, केंद्र में सरल कर दिये अब राज्यों में निवेश उन राज्यों में जाएगा जो अपनी व्यवस्थाएं सरल करेंगे! इसके बाद बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि देश की टैक्स व्यवस्था को सरल किया जाए |

अब उस टैक्स व्यवस्था को सरल करना ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है, What was the object behind the GST? India politically integrated into one country but economically we were different states, you have to have a free flow of goods and services across the country, you have to have a uniform rate of taxation throughout the country, you have to make the taxation rates more moderate this brings down the cost. You have to have one person being assessed once not by different tax authorities in a different way. इससे व्यवसाय में कितनी सरलता आती है, संविधान बदलना था, राज्य सरकारों को तैयार करना वो सारी व्यवस्था हम लोग लाए, डायरेक्ट टैक्स रिफार्म के लिए भी ये सरल काम नहीं है, कुछ ब्लैक मनी लोगों ने बाहर रखा हुआ था, कुछ देश के अन्दर है | आज मैं चाहूँगा लोग पढ़ें एक रिपोर्ट 2012-13 के taxes पे आई है | A large section of people who file returns don't pay taxes. तो इसलिए मैं रात को एक कार्यक्रम में था पीयूष जी के साथ तो उन्होंने कहा आपकी क्या दो उद्योग, इंडस्ट्री से अपेक्षाएं हैं, मैंने कहा दो अपेक्षाएं हैं | The first is the taxes which are dues must be paid and the second is when you take money from banks also please return in appropriately. इसके बगैर देश की इकॉनमी चल नहीं सकती, free trade is fair trade और fairness में अगर सरकार business friendly है तो उस atmosphere का हम लाभ उठाएं और पूरी दुनिया में हम देखें, कोई दुबई या सिंगापुर को हम लोग छोड़ दें तो बाकी विकसित देशों की तुलना में हमारे tax rates ज्यादा reasonable अब होते जा रहे हैं और इसलिए जो आशीष जी ने कहा वो सही कहा कि indirect tax rate भी कम आए लेकिन कम लाने के लिए ये भी ज़रूरी है उसका बेस बढे, और बेस बढ़ने के लिए ज़रूरी है हर व्यक्ति अपना टैक्स दे | जितने natural resources हैं, coal है, mineral है, spectrum है सरकार ने तय किया कि हमें कोई इसमें रुचि नहीं है किसी को लाभ देने में let it go by auctioning. ये विडम्बना है कि 26 महीने से मोदी जी की सरकार चल रही है और हमारा तो कोई जिक्र नहीं आता, आज भी स्कैंडल निकलते हैं तो पिछली सरकार के ही निकलते हैं! कारण ये है कि इस तरह की discretions हमने अपने हाथों में नहीं रखीं ! अभी चुनौतियां भी हैं और चुनौतियां ये हैं कि GST अब पारित होगया धीरे धीरे उसको समझौता करके एक टैक्स रेट बने, उसके लोकल लॉज़ बनें, जितनी जल्दी समन्वय होगा उतनी जल्दी लागू होगा! इसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के बैंकों को ताकत देना जिसमें सरकार लगी हुई है जिसके लिए हम बिलकुल मन बना चुके है वो करना है उसके बाद आगे का जो रास्ता है वो केंद्र और राज्य की सरकारें अब ये फेज आएगा implementation का, और इस implementation में जो मैंने आरम्भ में कहा infrastructure, investment, rural investment, concentrating on manufacturing, innovation, technology. और एक बार ये छवि बनजाये कि दुनिया के

बाकी देश धीमी गति पे हैं और हिंदुस्तान तेज़ गति से दौड़ रहा है, लोग डरते क्यूँ थे, डरते इसलिए थे कि आप निर्णय नहीं कर पाते, आज वो शिकायत नहीं है, डरते इस बात से थे कि आपके यहाँ मैंने निर्णय कर लिया ये निवेश करने का अब परमिशन मिलते-मिलते सालों निकल जाते हैं आज वो भी जल्दी मिल रही है, डरते थे कि आपकी टैक्स व्यवस्था unpredictable है, उसको हम केवल predictability की दिशा में ला रहे है, we are trying to create one of the most modern taxation setups in the world. डरते इसलिए थे कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है और ये तो सब मानते हैं कि उस बीमारी से भी हम लोगों ने निवारण पाया है, आपके यहाँ infrastructure बड़ा poor है, आपके यहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है ! अब ये एक एक शिकायत जो होती थी मोदी जी की सरकार और राज्यों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि इनमें से एक एक प्रश्न का उत्तर हमारे सामने हो और यही कारण है कि global investment इस देश की तरफ देख रहा है, today public investment has increased, Foreign Direct Investment has increased, private sector has to get out of that stress situation, hopefully a good monsoon will raise the demand this year, we will continue to strengthen, continue to invest in areas like infrastructure, continue to invest in rural India and then concentrate on our manufacturing sector where the growth potential is very high. और अगर इस परिस्थिति में, दुनिया में वापिस विकास और ग्रोथ वापिस आती है तो मुझे लगता है कि जैसे एशिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं तेज़ी से आगे बढ़ी थीं उस दिशा में भारत को आगे बढ़ना और एक लम्बे पीरियड के लिए high growth rate को sustain करना जिससे देश में ताक़त आपाए ये संभव है ! और मैं मानता हूँ कि GST पारित करने के पीछे जो public opinion का दबाव था उसकाबहुतयोगदान था और केंद्र और राज्य की सरकारें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं उस दिशा में बढती रहे उसके लिए उस दबाव को आप बनाए रखिए, वही देश की हित में रहेगा |

आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद!